NEERAJ®

शासन : मुद्दे और चुनौतियाँ

(Governance: Issues and Challenges)

B.P.A.G.-172

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Vaishali Gupta*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

शासन : मुद्दे और चुनौतियाँ
(Governance: Issues and Challenges)

Question Paper—June-2024 (Solved) 1

Question Paper—December-2023 (Solved) 1

Question Paper—June-2023 (Solved) 1

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved) 1

Sample Question Paper–1 (Solved) 1

Sample Question Paper–2 (Solved) 1

S.No. *Chapterwise Reference Book* *Page*

सरकार और शासन : अवधारणाएँ
(Government and Governance: Concepts)

1. वैश्वीकरण : राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका 1
(Globalisation: Role of State, Market and Civil Society)

2. शासन : अवधारणात्मक आयाम 11
(Governance: Conceptual Dimensions)

3. भारत में शासन का ढाँचा 19
(Governance Framework in India)

4. शासन में हितधारक 29
(Stakeholders in Governance)

शासन और विकास
(Governance and Development)

5. विकास के बदलते आयाम 39
(Changing Dimensions of Development)

6. शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती 49
(Strengthening Democracy through Governance)

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

शासन : उभरते दृष्टिकोण
(Governance : Emerging Perspectives)

7. शासन की चुनौतियाँ और नौकरशाही की बदलती भूमिका 58
(Governance Challenges and Changing Role of Bureaucracy)

8. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी और शासन 69
(Information and Communication Technology and Governance)

9. मीडिया की भूमिका (Role of Media) 80

10. कॉर्पोरेट शासन (Corporate Governance) 91

11. सतत् मानव विकास (Sustainable Human Development) 103

12. पारदर्शिता और जवाबदेही 112
(Transparency and Accountability)

स्थानीय शासन (Local Governance)

13. विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय शासन 122
(Decentralisation and Local Governance)

14. समावेशी और सहभागी शासन 134
(Inclusive and Participative Governance)

भारत में सुशासन की पहल
(Good Governance Initiatives in India)

15. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, नागरिक चार्टर, ... 144
सूचना का अधिकार, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
(Public Service Guarantee Act, Citizen's Charter,
Right to Information, Corporate Social Responsibility)

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS
www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

शासन : मुद्दे और चुनौतियाँ

(Governance: Issues and Challenges)

B.P.A.G.-172

समय : 3 घण्टे **अधिकतम अंक : 100**

नोट : *निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम से कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. वैश्वीकरण, राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-2, 'वैश्वीकरण और राज्य', पृष्ठ-3, 'वैश्वीकरण और बाजार', 'वैश्वीकरण और नागरिक समाज'

प्रश्न 2. संविधान के संचालन के ढाँचे तथा शासन में राज्यकर्ताओं की भूमिका की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-3, पृष्ठ-19, 'शासन के संचालन का ढाँचा : राज्यकर्ताओं की भूमिका'

प्रश्न 3. शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-6, पृष्ठ-50, 'शासन के द्वारा लोकतंत्र की मजबूती : कुछ उपाय'

प्रश्न 4. वर्तमान युग में शासन की चुनौतियों तथा नौकरशाही की बदलती भूमिका का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-7, पृष्ठ-62, प्रश्न 3, पृष्ठ-63, प्रश्न 4

भाग-II

प्रश्न 5. भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की पहलों को उजागर कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-70, 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी : भारत में पहल'

प्रश्न 6. ''समकालीन समय में शासन में मीडिया महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।'' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-9, पृष्ठ-80, 'मीडिया और शासन'

प्रश्न 7. सतत मानव विकास का अवलोकन दीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-104, 'सतत मानव विकास : अवलोकन'

प्रश्न 8. विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासन के आयामों का परीक्षा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-123, 'विकेन्द्रीकरण के आयाम तथा स्थानीय शासन'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

शासन : मुद्दे और चुनौतियाँ

(Governance: Issues and Challenges)

B.P.A.G.-172

समय : 3 घण्टे **अधिकतम अंक : 100**

नोट : *निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग से कम से कम दो प्रश्न अवश्य कीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।*

भाग-I

प्रश्न 1. वैश्वीकरण के वैचारिक ढाँचे को स्पष्ट कीजिए और इसके दृष्टिकोणों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-1, पृष्ठ-1, 'वैश्वीकरण : अवधारणात्मक ढाँचा', पृष्ठ-2, 'वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य'

प्रश्न 2. ''शासन की अवधारणा का प्रयोग कई संदर्भों में किया जाता है।'' टिप्पणी कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-2, पृष्ठ-12, 'शासन : प्रासंगिक प्रयोग'

प्रश्न 3. शासन प्रक्रिया के हितधारक भागीदारी के रूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-4, पृष्ठ-32, प्रश्न 3

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

(क) सतत् विकास लक्ष्य

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-5, पृष्ठ-46, प्रश्न 5

(ख) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी : विकासमूलक दृष्टिकोण

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-8, पृष्ठ-68, 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी : विकासात्मक दृष्टिकोण'

भाग-II

प्रश्न 5. निगमित शासन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और इसके सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-10, पृष्ठ-94, प्रश्न 1, पृष्ठ-92, प्रश्न 2

प्रश्न 6. जवाबदेही की अवधारणा की व्याख्या कीजिए और पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रासंगिकता का उल्लेख कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-112, 'जवाबदेही का अर्थ', पृष्ठ-115, प्रश्न 2

प्रश्न 7. शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-13, पृष्ठ-125, 'शहरी क्षेत्र निकाय की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन'

प्रश्न 8. निम्नलिखित में से प्रत्येक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए–

(क) मानव विकास की अवधारणा

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-11, पृष्ठ-103, 'मानव को समझना'

(ख) नागरिक घोषणा-पत्र

उत्तर–संदर्भ–देखें–अध्याय-12, पृष्ठ-113, 'नागरिक घोषणा-पत्र'

■■

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

Sample Preview
of
The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

शासन : मुद्दे और चुनौतियाँ
(Governance: Issues And Challenges)

सरकार और शासन : अवधारणाएँ
(Government and Governance: Concepts)

वैश्वीकरण : राज्य, बाजार और नागरिक समाज की भूमिका
(Globalisation: Role of State, Market and Civil Society)

1

परिचय

वैश्वीकरण की अवधारणा बहुआयामी है। अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया व्यापार में बाधाओं तथा अवरोधों को दूर कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाने तथा देश में बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश को बढ़ावा देने पर विचार करती है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वैश्वीकरण दुनिया भर के सभी स्थानों को वैश्विक स्तर पर एकीकृत आर्थिक प्रणाली में शामिल करने के लिए पूँजीवाद के विस्तार को संदर्भित करती है। सांस्कृतिक रूप से यह वैश्विक प्रसार, विचारों, मूल्यों, मानदंडों, व्यवहारों और जीवन के तरीकों के एकीकरण को संदर्भित करती है। समाजशास्त्रियों के अनुसार, वैश्वीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, जिसमें समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में परस्पर परिवर्तन शामिल है। एक प्रक्रिया के रूप में, इसमें राष्ट्रों, क्षेत्रों, समुदायों और यहां तक कि अलग-थलग स्थानों के बीच इन पहलुओं का लगातार बढ़ता एकीकरण शामिल है। राजनीतिक रूप से, यह वैश्विक स्तर पर संचालित शासन के रूपों के विकास को संदर्भित करता है, जिनकी नीतियों और नियमों का राष्ट्रों से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। वैश्वीकरण के ये तीन मुख्य पहलू तकनीकी विकास, संचार प्रौद्योगिकियों के वैश्विक एकीकरण और मीडिया के वैश्विक वितरण से प्रेरित हैं।

अध्याय का विहंगावलोकन

वैश्वीकरण : अवधारणात्मक ढाँचा

21वीं शताब्दी में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कर्ताओं, विद्वानों, नागरिकों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संस्थानों के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हुई है। वैश्वीकरण आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी बदलावों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिससे राष्ट्रीय सीमाएं संकुचित हो जाती हैं तथा माल, सेवाओं और पूँजी के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को गति प्रदान की जाती है। इसे आहार तथा संस्कृति के मेकडोनलडवाद, उपभोक्ता रुचियों की समरूपता तथा सामूहिक शक्ति और निर्धनता में वृद्धि के साथ उदार लोकतांत्रिक विचारों के प्रसार को उत्तरदायी माना गया है।

वैश्वीकरण के जटिल प्रक्रमों को एक से अधिक तरीकों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। हेलीनर के अनुसार, वैश्वीकरण की दोहरी प्रक्रिया के अंतर्गत परिवहन, संचार और सूचना संसाधन की प्रौद्योगिकी उन्नति, समय और दूरी में संकुचन और विश्व के एक भाग में लिए जाने वाले निर्णयों का प्रभाव विश्व के अन्य हिस्सों पर है, जिससे संपूर्ण विश्व को वैश्विक ग्राम की संज्ञा दी जाने लगी है। ओझा के अनुसार, वैश्वीकरण राज्य के चुनौतीपूर्ण अधिकार और कल्याणकारी कार्यों के अपरिवर्तनीय परिवर्तनों के अनुकूलन की प्रक्रिया है तथा विकासशील देशों के विषय में इसे अनुभव किया जा सकता है।

वैश्वीकरण का उद्भव

वैश्वीकरण के प्रादुर्भाव का काल निर्धारित नहीं है। नायर के विचार में वैश्वीकरण की उत्पत्ति मध्यकाल के बाद यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के रूप में हुई। 16वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के साथ इसे गति प्राप्त हुई और औद्योगीकरण अवस्था में यह सुदृढ़ हुई। ब्रिटिश उदारवाद के साथ इसकी जड़ें मजबूत होती गईं तथा अमेरिकी राजनेताओं से प्राप्त बौद्धिक शक्ति और वैश्विक आर्थिक संस्थानों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप यह प्रबल हुई, जिसके अंतर्गत गैट (GATT), विश्व व्यापार संगठन तथा ब्रेटन वुड्स व्यवस्था सम्मिलित थे। रॉबर्टसन द्वारा वैश्वीकरण की संरचना पाँच पहलुओं में प्रस्तुत की गई है–

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

1. **1400-1750**—यूरोप में ईसाई जगत का समापन और राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव विकास की प्राथमिक अवस्था को संदर्भित करता है।
2. **1750-1875**—यूरोप में राज्य के नव-निर्माण तथा अंतर्राष्ट्रवाद और विश्ववाद का आरंभ प्रारंभिक चरण को दर्शाता है।
3. **1875-1925**—प्रस्थान की इस अवस्था के अंतर्गत है, वैश्विक समुदाय, वैश्विक कैलेंडर, प्रथम विश्वयुद्ध तथा विश्वव्यापी प्रवास और राष्ट्र राज्य के अंतर्राष्ट्रीय क्लब में गैर यूरोपीय लोगों का समावेश हुआ।
4. **1925-1969**—सौहार्द चारण के अंतर्गत शीत युद्ध, राष्ट्र संघ तथा संयुक्त राष्ट्र की विरासत का गठन तथा तृतीय विश्व का प्रादुर्भाव हुआ।
5. **1969-1992**—अनिश्चित काल की इस अवस्था के अंतर्गत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण तथा वैश्विक पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और वैश्विक जनसंचार माध्यमों का विकास हुआ।

1980 के अंत और 1990 के आरंभिक वर्षों में आर्थिक और राजनीतिक विकास के परिणामस्वरूप वैश्वीकरण का उदय हुआ और समाजवादी राज्य का पतन, बर्लिन की दीवार गिरना तथा पश्चिमी आर्थिक उदारवाद जैसे महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमों के चलते राज्य के उद्योगों का निजीकरण, अनियमितता तथा बजट में कटौती देखी गई। बैंकिंग प्रणाली की अनियमितता, व्यापार विनिमय दरों का उदारीकरण तथा निवेश और प्रौद्योगिकी के विकास के परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निगमों का विस्तार हुआ।

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य

आर्थिक परिप्रेक्ष्य—वैश्वीकरण के आर्थिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वैश्वीकरण को नव-पूँजीवाद की शाखा के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार का विकास हुआ। इसके परिणामस्वरूप सीमापार वित्त प्रवाह तथा समन्वय में आसानी होती है तथा स्थानिक अवरोध कम हो जाते हैं। पैट्रास के अनुसार, राजनीतिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वैश्विक पूँजी का विस्तार हुआ, जिसके फलस्वरूप न केवल तकनीकी बदलाव आये, अपितु यूरोप और एशिया के साम्यवादी देशों का पतन हुआ। साम्राज्यवाद और पूँजीवाद का वर्चस्व कायम हुआ। स्केलेर का मत था कि वैश्विक पूँजीवादी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को प्रभावित तथा नियंत्रित करती है तथा वैश्विक पूँजीपति वर्ग व्यापार का संचालन करता है। दूसरी ओर कास्टेल्स के अनुसार, वैश्विक पूँजीवादी वर्ग नहीं, अपितु एकीकृत वैश्विक पूँजी प्रधान नेटवर्क ने अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया, जिससे समाज प्रभावित हुआ। कास्टेल्स के अनुसार, नेटवर्क हमारे समाज के नए सामाजिक आकारों का निर्माण करता है।

सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य—वैश्वीकरण का सामाजिक-सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य गिडेन्स, रॉबर्टसन और वॉटर्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। गिडेन्स, समय स्थान भेद प्रक्रिया के द्वारा वैश्वीकरण की संकल्पना को आधुनिकता के उत्पाद के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों को उद्धृत किया गया तथा सामयिक और स्थानिक रूप से इसका पुनर्निर्माण किया गया। सामाजिक संबंधों के विस्तृत नेटवर्क द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों को संगठित किए जाने पर बल दिया गया। रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण की विश्व के दबाव और समग्र रूप से विश्व की चेतना की महानता की प्रक्रिया के रूप में व्याख्या की है। वॉटर्स ने वैश्वीकरण को राज्य सामाजिक प्रक्रिया के रूप में चित्रित किया, जिसके कारण क्षेत्रीय बाधाएं अप्रासंगिक होती जा रही हैं तथा भौगोलिक बाधाएं लोगों में जागरूकता का विकास कर रही हैं। वॉटर्स ने वैश्वीकरण को अर्थशास्त्र या राजनीति की बजाए संस्कृति से जोड़कर देखा है तथा मूल्यों, अभिरुचियों, रुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतीकों के माध्यम से संबंधों के सुव्यवस्थित प्रबंध की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया है। वैश्वीकरण का संबंध उपभोक्ता, संप्रभुता तथा व्यक्तिगत, एकीकृत और विस्तारित तकनीकी नवाचार से भी है।

वैश्वीकरण और राज्य

वैश्वीकरण आर्थिक तथ्य के साथ-साथ राजनीतिक तथ्य से भी जुड़ा है। इस पर प्रभुसत्ता संपन्न सरकार, निजी निगम, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, जैसे—विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड, विश्व व्यापार संगठन आदि से जुड़े जटिल समझौतों का भी प्रभाव पड़ता है। नव उदारवादी नीतियों द्वारा निर्देशित वैश्वीकरण का उद्देश्य आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व के द्वारा पूँजीपतियों का विस्तार करना है। मैकमिशल ने राज्यों पर बहुपक्षीय एजेंसियों, वैश्विक फर्मों तथा वैश्विक और क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों के दबाव से उत्पन्न अवरोधों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव में उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का विस्तार हुआ।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप राज्य की भूमिका कम हो जाती है तथा अनेक आर्थिक गतिविधियों को बाजार द्वारा अधिकृत कर लिया जाता है। राज्य के संकुचन और बाजार की वृद्धि में आनुपातिक संबंध पाया जाता है तथा संतुलन एवं श्रम के विभाजन के लिए बाजार सर्वोत्तम स्थान समझा जाता है। राजनीतिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप बाजार के विस्तार में अवरोध उत्पन्न नहीं हो, अत: राज्य से दूर रहना बेहतर समझा जाता है। यद्यपि राज्य की स्वायत्तता कम नहीं हुई, परंतु इसका स्वरूप परिवर्तित होकर कल्याणकारी से प्रतिस्पर्धात्मक हो गया। राज्य की कॉर्पोरेट भूमिका के परिणामस्वरूप जनता का सार्वजनिक क्षेत्र में स्थान कम होता जाता है। इसके अतिरिक्त प्रशासन के बाजारीकरण, नौकरशाही में वृद्धि, संरचनाओं का विघटन, परिवर्तनशील उत्पादन व्यवस्था राष्ट्र-राज्य द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं के नियंत्रण में कमी तथा बाजार द्वारा निर्देशित सरकार को प्राथमिकता दी जाती है। वैश्वीकरण

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

के अनुसार राज्य कुछ वैश्विक मानकों का पालन करने के लिए बाध्य है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया में राज्य तीन प्रकार से हस्तक्षेप करता है–कार्यात्मक, संस्थागत तथा रणनीतिक। कार्यात्मक हस्तक्षेप के अंतर्गत बाजार की असफलताओं को सुधारा जाता है। संस्थागत हस्तक्षेप बाजार के कार्यकर्ताओं के लिए कार्य क्षेत्र के नियमों का निर्धारण कर बाजार को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। रणनीतिक हस्तक्षेप के माध्यम से बाजार का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। राज्य बाजार संचालन के लिए संवैधानिक तथा कानूनी सिद्धांतों की रूपरेखा तथा सामाजिक और आर्थिक प्रारूप और संपत्ति पर अधिकार से संबंधित कानूनी नियमों का निर्धारण करता है।

वैश्वीकरण और बाजार

वैश्वीकरण के माध्यम से बाजार का कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है तथा राज्य की भूमिका गौण हो जाती है। वैश्वीकरण वैश्विक बाजार के गति के नियम निर्धारित करता है। बाजार में माँग और आपूर्ति के नियम के आधार पर प्रतिस्पर्धा और स्व-नियमन निर्धारित होता है। वैश्वीकरण सीमित सरकार तथा सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण एवं वितरण को बढ़ावा देता है। राज्य की अपेक्षा बाजार मानव आकांक्षाओं को बेहतर रूप से पूरा करता है। वैश्विक बाजार से अभिप्राय राष्ट्र-राज्यों के नियंत्रण वाले भू-राजनीतिक सीमाओं से परे एक स्थान है। वैश्विक बाजार के महत्त्वपूर्ण प्रभाव हैं–बाहरी व्यापार तथा वित्त के मार्ग में आने वाले अवरोधकों को दूर करके अर्थव्यवस्था का विनियमन, आर्थिक विकास तथा वित्त के अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता के नियंत्रण के उन्मूलन, पूँजी निवेश का विस्तार, निजीकरण और स्थानीय तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन, मुक्त बाजार तथा पूँजीवाद की गतिशीलता।

वैश्विक बाजार की उत्पत्ति 1980 के दशक में हुई। इसने विश्वभर में पूँजीवाद के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। वैश्वीकरण ने बाजारों के विस्तार के लिए देशों से आर्थिक उदारवाद को सम्मिलित करने का अनुरोध किया। वैश्वीकरण के महत्त्वपूर्ण परिणाम हैं–

- बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तियों को क्रय, विक्रय तथा निवेश से संबंधित अधिक स्वतंत्रता,
- लाभ अधिकतमीकरण के लिए जोखिम विविधता तथा संसाधन में निवेश के अवसर,
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को अधिक आय,
- प्रौद्योगिकी का आंतरिक हस्तांतरण एवं तकनीकी जानकारी आदि।

वैश्वीकरण और नागरिक समाज

वैश्वीकरण व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू यथा-आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा संचालित बाध्यकारी शक्ति है, जो जनसंचार के द्वारा राज्य की शक्तियों को सीमित करते हुए व्यक्तियों पर नियंत्रण कायम कर दूरवर्ती स्थलों के अधीन करती है। बहुराष्ट्रीय निगम बहुराष्ट्रीय बैंकों की सहायता से वितरण एवं अन्य संसाधन प्राप्त करके लाभ और शक्ति का विस्तार करते हैं, जिसके चलते अमीर अधिक अमीर तथा गरीब अधिक गरीब होते जाते हैं। वैश्वीकरण के दुष्परिणामों में पर्यावरणीय प्रदूषण तथा सांस्कृतिक गिरावट प्रमुख हैं।

नागरिक समाज आर्थिक एवं राज्य के बीच के क्षेत्र को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप यह परिवार, संघ तथा राज्य से दूर हो गया है क्योंकि यह उच्चतम अधिकृत राज्य द्वारा निर्मित औपचारिक नियमों के अनुसार कार्य करता है। कॉलडोर के अनुसार, नागरिक समाज के विकास के माध्यम से ही नागरिक, राज्य और अन्य केंद्रों के साथ सामाजिक अनुबंध पर समझौता करते हैं।

डायमंड के संस्थागत दृष्टिकोण के अनुसार, नागरिक समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक, अनौपचारिक और शैक्षिक संगठनों के अतिरिक्त हित आधारित संगठन, विकासात्मक संगठन, राजनीतिक संगठन तथा सामाजिक और भावनात्मक संस्थान भी मौजूद होते हैं। ये सभी संगठन राज्य से स्वायत्तता प्राप्त करते हैं। नागरिक समाज के संगठन व्यक्तिगत हितों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए समूहों के नेटवर्क हैं, जिसमें स्थानीय एवं बाह्य वित्तीय, निजी, परोपकारी, सामाजिक, विकासात्मक और व्यावसायिक संगठन सम्मिलित हैं।

नागरिक समाज के साथ कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन पर्यावरण और सामाजिक विषयों से जुड़े होते हैं। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक नागरिक समाज की उत्पत्ति हुई है, जो वैश्विक स्तर पर स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों का अभिसरण है तथा सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विस्तारित भौगोलिक क्षेत्रों में संलग्न नेटवर्क द्वारा स्थानिक पृथक्करण को पार करती है। वैश्विक नागरिक समाज के अंतर्गत गैर-लाभकारी व्यवसाय, सामाजिक आंदोलन, पर्यटक, शिक्षाविद्, कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार, नृजातीय और भाषाई समूह आदि सम्मिलित हैं। पर्यावरणीय अधिकारों के संरक्षण, शिक्षा का समर्थन, महिलाओं का विकास, जाति और धार्मिक आदि सभी वैश्विक नागरिक समाज द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसे फाल्क ने 'नीचे से वैश्वीकरण' तथा अप्पादुराई ने 'जमीनी स्तर पर वैश्वीकरण' की संज्ञा दी है। बोहमान के अनुसार, वैश्विक नागरिक समाज सार्वजनिक क्षेत्रों की तीन विशेषताएँ अपनाता है–सार्वजनिक विमर्श में भाग लेना, स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों का अनुपालन तथा अभिकर्ता को अनिश्चित दर्शकों तक पहुँचना।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं?

उत्तर–वैश्वीकरण से आशय विश्व के विभिन्न समाजों और अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है। यह उत्पादों, विचारों,

NEERAJ PUBLICATIONS www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

www.neerajbooks.com

दृष्टिकोणों, विभिन्न सांस्कृतिक पहलुओं आदि के आपसी विनिमय के परिणाम से उत्पन्न विचार है। इसके कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अन्त:निर्भरता में वृद्धि होती है। वहीं पश्चिमीकरण का आशय ऐसी प्रक्रिया से है, जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न पहलुओं यथा–भाषा, रहन-सहन, उद्योग, प्रौद्योगिकी, आर्थिक गतिविधि, राजनीति आदि में पश्चिमी विशेषताओं का समावेश होने लगता है। वैश्वीकरण कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन अवधारणा है। इसका बीज पाश्चात्य पूँजीवाद व उपनिवेशवाद में देखा जा सकता है और जिसने अन्य देशों के संसाधनों पर नियंत्रण के रूप में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इससे पूर्व भी प्राचीन काल में प्रसिद्ध रेशम मार्ग द्वारा भी भारतीय उपमहाद्वीप सहित चीन, फारस, यूरोप और अरब देशों के साथ व्यापार-वाणिज्य के माध्यम से सभ्यताओं के बीच अंतर्क्रिया बढ़ी।

वैश्वीकरण मानव इतिहास में हाल ही में गढ़ा गया शब्द है। यह वैश्विक निगमों और संस्थानों के आगमन की विशेषता है, जो कई देशों में काम करते हैं, जैसे कि उनके बीच कोई वास्तविक सीमा नहीं है और विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण, एक सामान्य वैश्विक पहचान और चेतना के लिए अग्रणी है। 2000 में, आईएमएफ ने वैश्वीकरण के चार बुनियादी पहलुओं की पहचान व्यापार और लेन-देन, पूँजी और निवेश आंदोलन, लोगों के प्रवास और ज्ञान के व्यापक प्रसार के रूप में की।

वैश्वीकरण की कोई एकल स्वीकृत परिभाषा नहीं है क्योंकि इसके बहुआयामी पहलू हैं, जिन्हें सटीक रूप से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। वैश्वीकरण विश्व के विचारों और संस्कृति के आदान-प्रदान से उत्पन्न होने वाली अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण की एक प्रक्रिया है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण दुनिया के संपीड़न और समग्र रूप से दुनिया की चेतना की गहनता को संदर्भित करता है।

वैश्वीकरण को विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों की गहनता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो दूर के इलाकों को इस तरह से जोड़ते हैं कि स्थानीय घटनाएं कई मील दूर होने वाली घटनाओं से आकार लेती हैं। इसके विपरीत यह एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है क्योंकि ऐसी स्थानीय घटनाएँ उन बहुत दूरगामी संबंधों से विपरीत दिशा में आगे बढ़ सकती हैं, जो उन्हें आकार देते हैं। स्थानीय परिवर्तन वैश्वीकरण का उतना ही हिस्सा है, जितना समय और स्थान में सामाजिक संबंधों का पार्श्व विस्तार।

वैश्वीकरण समकालीन सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में, सांस्कृतिक से लेकर अपराधी तक, वित्तीय से आध्यात्मिक तक, दुनिया भर में अंतर्संबंध का विस्तार, गहनता को तेज करना है। जब वैश्वीकरण की परिभाषाओं को एक साथ रखा जाता है, तो वैश्वीकरण की पाँच आवश्यक विशेषताओं की पहचान की जा सकती है, जो इस प्रकार हैं–

- प्रकृति में वैश्विक-अर्थशास्त्र, राजनीति, संस्कृति आदि के लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार।
- इनपुट के साथ-साथ पहुँच में विश्व स्तर पर समावेश। दुनिया के एक हिस्से के विचार/उत्पाद दुनिया के दूसरे हिस्से में उसी का विस्तार हैं।
- व्यापार, समाज आदि के कई पहलुओं के बीच अन्योन्याश्रयता।
- उन संबंधों में स्थिरता और नियमितता।
- केवल 'कुलीन' नहीं, 'जनता' को शामिल करना चाहिए। एक वैश्विक चेतना का अस्तित्व, जिसमें ग्रह पर सभी लोगों को शामिल किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ चुनिंदा लोगों को।

प्रश्न 2. वैश्वीकरण के उद्‌भव के कारण स्पष्ट कीजिए।

उत्तर–रॉबर्टसन के अनुसार, वैश्विक घनत्व और जटिलता के एक बहुत ही उच्च स्तर की वर्तमान स्थिति के लिए अस्थायी-ऐतिहासिक पथ को पाँच चरणों में चित्रित किया जा सकता है। उनका मॉडल अपेक्षाकृत हाल के इतिहास में प्रमुख बाधा प्रवृत्तियों पर जोर देता है और प्राथमिक कारकों और वैश्वीकरण के प्रमुख तंत्र के बारे में कोई बड़ा दावा नहीं करता है। वैश्वीकरण के उद्‌भव के निम्नलिखित कारण हैं–

1. संचार व सूचना क्रांति–वैश्वीकरण का मुख्य स्रोत संचार एवं सूचना का तीव्र होना है। 1990 के बाद के वर्षों में संचार क्षेत्र में सूचना क्रांति ने उपग्रह, टेलीविजन, इंटरनेट आदि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समस्त विश्व के साथ जोड़ दिया है। सूचनाओं से व्यक्ति की सोच प्रभावित हुई है। इसने लोगों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावनाओं को कमजोर किया है।

आज विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ संचार और सूचना तकनीकी ने अपना अस्तित्व पेश न किया हो और राजनीति, अर्थशास्त्र एवं समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं है, जो कि कम्प्यूटर, तकनीक के प्रभाव से मुक्त हो। आज प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को मदद देने में तकनीक लाभदायक है। इसलिए लोग वैश्वीकरण के बारे में चिंतन करने लगे हैं।

2. शीत युद्ध का अंत–द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् तत्कालीन सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध आरम्भ हुआ था, यह युद्ध विचारगत था। सोवियत संघ साम्यवाद का प्रतीक था और अमेरिका उदारवादी लोकतंत्र का समर्थक था, किन्तु दिसम्बर 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया।

अब अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अमेरिका वैश्वीकरण एवं पूँजीवाद का समर्थक था। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों ने लोकतंत्र के मूल्यों को स्वीकार किया गया तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ा मिला।

3. पूर्व सोवियत संघ का पतन–पूर्व सोवियत संघ के पतन के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक नई प्रवृत्तियों ने

www.neerajbooks.com